

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत): माननीय उपसभापति महोदय, मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व मिलने के बाद, जिसमें नशा मुक्ति कराना भी एक विषय है, हमने इस विषय की गम्भीरता को महसूस करते हुए कि पहले क्या हुआ है और अभी क्या करना चाहिए, नशा मुक्ति के लिए जो 2012 से नीति बनी हुई है, उस नीति में और क्या किया जाना चाहिए, इन सब विषयों पर गम्भीरता से विचार किया और यह पाया कि इसका detailed survey होना चाहिए था। अभी तक यह पता नहीं है कि देश में नशे में लिप्त लोग कितने हैं। जो प्रारम्भिक आंकड़ा सामने आया है, वह 7 करोड़ 21 लाख के आसपास है। हमने देखा कि हर 5 साल में सर्वे कराने का प्रावधान है, परन्तु 2001 के बाद किसी प्रकार का कोई सर्वे नहीं हुआ है। एक सैम्पल सर्वे कराया गया था, जिसके आंकड़े भी ठीक से उपलब्ध नहीं हुए। तो हमने निर्णय लिया है कि इस मामले में देश में ख्याति प्राप्त एम्स की एक संस्था है, वह यह काम करती रहती है, उससे अनुबन्ध किया है।...(व्यवधान)...

श्री प्रेम चन्द गुप्ता : सर ...(व्यवधान)... इस पर डिबेट करा लीजिए।...(व्यवधान)...

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, हम उसको सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराएँगे और वह सर्वे करके 2018 तक जानकारी उपलब्ध कराएगी।

जहाँ तक पंजाब का सवाल है, तो हमने पंजाब में अभी इन दो वर्षों के अन्दर-अन्दर नशा मुक्ति के लिए 28 नये केन्द्र खोले हैं। इसके 7 केन्द्र पहले से थे और 28 नये केन्द्र अब खोले हैं। हमारी सीधी मंशा पंजाब में नशा सेवन कम कराने की है। हमने वहाँ के मुख्य मंत्री जी से, वहाँ के उप मुख्य मंत्री जी से और सम्बन्धित अधिकारियों से बातचीत की है और पंजाब में नशा मुक्ति के लिए हम वे सारी सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हैं।

सर, जो प्रश्न रोकथाम के सम्बन्ध में आया था, तो हम गृह मंत्रालय से, स्वास्थ्य मंत्रालय से तथा अपने मंत्रालय से इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि सप्लाई कम हो और नशे में लिप्त लोग नशा छोड़ें तथा इनकी संख्या आगे नहीं बढ़े।

Compulsory Urdu education in schools

*197. SHRI MD. NADIMUL HAQUE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government is planning to make Urdu education compulsory in schools, if so, the details thereof and the reasons therefor;

(b) whether Government plans to modify the three-language policy, where students learn English, Hindi and their local language in schools, if so, the details thereof and the reasons therefor;

(c) whether the three-language policy has succeeded in creating a uniform medium of communication across the country; and

(d) the details of the percentage of students who learn English and Hindi in schools, State-wise?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir.

(b) No such proposal is currently under consideration.

(c) The major objective of three language formula is to promote language harmony and equality among languages in school education by making provision for the study of three languages.

(d) The information is being collected from the States and Union Territories and will be laid on the Table of the House.

SHRI MD. NADIMUL HAQUE: Sir, before putting my question, I would like to say that all the parties have given a notice for a Short Duration Discussion on the new Education Policy. That should be taken up on Monday. Now, I come to my question.

सर, जब उर्दू की बात होती है, वहीं मिर्जा ग़ालिब का नाम आता है। हम लोग ग़ालिब को पसन्द करते हैं, लेकिन 1969 में जब ग़ालिब सदी तक़रीबात मनायी जा रही थी, उस वक़्त साहिर लुधियानवी जी ने कहा था:

"जिस अहदे सियासत ने जिन्दा ज़बां कुचली,
उस अहदे सियासत को महरूमों का ग़म क्यों है?
ग़ालिब जिसे कहते थे, उर्दू का ही शायर था,
उर्दू पर सितम ढाकर, ग़ालिब पर करम क्यों है?"

सर, आज भी लगभग यही हालात हैं और यह सौतेला सुलूक जारी है। मेरा सवाल यह है कि किसी भी ज़बान को बचाने के लिए जरूरी है कि उसे रोजी-रोटी से जोड़ा जाए, लेकिन सरकारी और सरकारी तावुन से चलने वाले उर्दू मीडियम स्कूलों की पूरे मुल्क में बहुत बुरी हालत है। एक तरफ़ उन स्कूलों में टीचर्स की पोस्ट्स खाली हैं और दूसरी तरफ़ उन खाली असाभियों को सिर्फ़ एससी/एसटी उम्मीदवारों से ही पुर किया जा सकता है। सर, बेश्तर एससी/एसटी उम्मीदवार उर्दू जानते नहीं और

जो लोग उर्दू से वाकिफ हैं, उनको ये नौकरियाँ नहीं मिल सकतीं। ऐसी सूरते हाल को हल करने के लिए मंत्री जी क्या करेंगे?

†[سر، جب اردو کی بات ہوتی ہے، وہیں مرزا غالب کا نام آتا ہے۔ ہم لوگ غالب کو پسند کرتے ہیں، لیکن 1969 میں جب غالب صدی تقریبات منائی جا رہی تھی، اس وقت ساحر لدھیانوی جی نے کہا تھا :

جس عہد سیاست نے زندہ زبان کچلی،
اس عہد سیاست کو محروموں کا غم کیوں ہے؟
غالب جسے کہتے تھے، اردو کا ہی شاعر تھا،
اردو پر ستم ڈھا کر، غالب پر کرم کیوں ہے؟

سر، آج بھی لگ بھگ یہی حالات ہیں اور یہ سوئیلا سلوک جاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی زبان کو بچانے کے لئے ضروری ہے کہ اسے روزی روٹی سے جوڑا جائے، لیکن سرکاری اور سرکاری تعاون سے چلنے والے اردو میڈیم اسکولوں کی پورے ملک میں بہت بری حالت ہے۔ ایک طرف ان اسکولوں میں ٹیچرس کی پوسٹس خالی ہیں اور دوسری طرف ان خالی اسامیوں کو صرف ایس۔سی۔/ایس۔ٹی۔ امیدواروں سے ہی پُر کیا جا سکتا ہے۔ سر، بیشتر ایس۔سی۔/ایس۔ٹی۔ امیدوار اردو جانتے نہیں اور جو لوگ اردو سے واقف ہیں، ان کو یہ نوکریاں نہیں مل سکتیں۔ ایسی صورت حال کو حل کرنے کے لئے منتری جی کیا کریں گے؟]

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put question. How much time do you need to put the question?

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, वैसे तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसी हमारी सारी भारतीय भाषाएँ हैं, वे अपनी बहुत सी विशेषताओं के साथ आती हैं, वैसे ही उर्दू एक बहुत ही बेहतरीन ज़बान है तथा इसका विकास और सभी भारतीय भाषाओं का विकास हो, यही सरकार का प्रयास है। इसलिए उर्दू के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं और जो आपके सुझाव भी होंगे तथा जैसा आपने फरमाया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे का जो बिन्दु है, उस पर हम चर्चा करेंगे, वहीं से हमारी चर्चा भी होगी। उसमें और भी बिन्दु आएं, लेकिन पहली से बारहवीं तक के सभी विषयों की उर्दू की किताबें तैयार हैं। आपने शिक्षक का उल्लेख किया कि प्रशिक्षक अच्छे होने चाहिए। इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी textbooks for B.Ed. courses have also been developed और जो नया curriculum framework बना, उसके अनुसार जो नई किताबें बनी हैं, वे सारी किताबें भी प्रिंट होकर तुरंत उपलब्ध हो जाएंगी। उसके साथ-साथ जैसे एनसीईआरटी regular basis पर ...**(व्यवधान)**...

श्री मो. नदीमुल हक: सर, यह जवाब नहीं है।

[جناب محمد ندیم الحق: سر، یہ جواب نہیں ہے۔]

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, वही मैं बता रहा हूँ ऐसा है कि यह जाति से संबंधित मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भाषा के विकास का मुद्दा है। भाषा में सबको मिलना चाहिए ... (व्यवधान)...

श्री मो. नदीमुल हक: सर, यह बहुत बड़ी practical problem है। हर जगह स्कूल में उर्दू टीचर्स की जगहें खाली हैं। इनको कैसे भरा जाएगा?

[جناب محمد ندیم الحق: سر، یہ بہت بڑی practical problem ہے۔ ہر جگہ اسکول میں اردو ٹیچرس کی جگہیں خالی ہیں، ان کو کیسے بھرا جائے گا؟]

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, वही मैं बता रहा हूँ हमारे देश में शिक्षा क्षेत्र में लगभग 25 परसेंट टीचर्स की कमी है। उसको भरने के लिए हम एक बेहद बेहतरीन योजना पर विचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी टीचर्स की भर्ती हो, इसको हम देखेंगे।

श्री मो. नदीमुल हक: सर, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। सर, पश्चिमी बंगाल में जब मां, माटी, मानुष की सरकार आई, तो उसने उर्दू के फरोग के लिए बहुत काम किया है। दिसम्बर, 2012 में Official Language Act में तरमीम करके उर्दू के साथ-साथ 5 दीगर ज़बानों को भी उसका जायज़ हक दिया। पश्चिमी बंगाल में उर्दू ज़बान बंगला के साथ रहते हुए जिस तरह परवाज़ चढ़ रही है, वह इस बात का इज़हार है कि हिन्दुस्तान की सभी ज़बानें एक-दूसरे की ताकत हैं। सर, मगरिबी बंगाल उर्दू अकादमी का बजट पिछले 5 सालों में 96 लाख से बढ़ा कर 15 करोड़ रुपए कर दिया गया है, इस मांग के साथ कि NCPUL के बजट में भी इज़ाफा किया जाए।

[جناب محمد ندیم الحق: سر، سب میرے چاہنے والے ہیں، میرا کوئی نہیں، میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں۔ سر، مغربی بنگال میں جب ماں، ماٹی، ماٹش کی سرکار آئی تو اس نے اردو کے فروغ کے لیے بہت کام کیا ہے۔ دسمبر 2012 میں Official Languages Act میں ترمیم کر کے اردو کے ساتھ ساتھ پانچ دیگر زبانوں کو بھی اس کا جائز حق دیا۔ مغربی بنگال میں اردو زبان بنگلہ کے ساتھ رہتے ہوئے جس طرح پروان چڑھ رہی ہے، وہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہندستان کی سبھی زبانیں ایک دوسرے کی طاقت ہیں۔ سر، مغربی بنگال اردو اکادمی کا بجٹ پچھلے پانچ سالوں میں 96 لاکھ سے بڑھا کر 15 کروڑ کر دیا گیا ہے، اس مانگ کے ساتھ کہ NCPUL کے بجٹ میں بھی اضافہ کیا جائے۔]

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put the question. Why do you say all this?
...(Interruptions)... No, no. There is no time. Please put your question.

श्री मो. नदीमुल हक: सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार मुल्कगैर पैमाने पर उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने के बारे में सोच रही है? सरकार चाहे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, ज़बान के लिए भी, ज्ञान के लिए भी, विज्ञान के लिए भी और हिन्दुस्तान के लिए भी।

†جناب محمد ندیم الحق: سر، میں آپ کے توسط سے مانتے منتری جی سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا سرکار ملک گیر پیمانے پر اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے؟ سرکار چاہے تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے، زبان کے لیے بھی، گیان کے لیے بھی، وگیان کے لیے بھی اور ہندستان کے لیے بھی۔

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, मैं नदीमुल हक से बहुत हद तक सहमत हूँ कि भाषा के विकास के लिए जो भी प्रयास करने चाहिए, वे करने चाहिए। उसमें मैं इतना ही कहूंगा कि राज्य सरकारें, क्योंकि हर राज्य में अलग-अलग परिस्थिति होती है और शिक्षा का विषय Concurrent List में होने के कारण राज्य सरकार इस पर उचित निर्णय लेती है। बहुत राज्यों ने उसके बारे में निर्णय लिया है। हम भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने बजट का उल्लेख किया। हमने पिछले दो वर्ष में 62-62 करोड़ रुपए केवल National Council for Promotion of Urdu Language के लिए रखे। उसका उपयोग बेहतरीन हो, उससे भाषा का सही प्रचार-प्रसार हो और ढंग से उसका विकास हो, यही हमारा प्रयास है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Chaudhary Munavvar Saleem. Please be brief.

चौधरी मुनव्वर सलीम: मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहता हूँ कि वह उर्दू, जिसने मोहब्बत और इन्क़लाब शब्द को अपनी कोख से जन्म दिया, वह उर्दू, आज मोहब्बत की मोहताज है और ये चाहें, तो उसको इंसाफ दे सकते हैं। नवोदय और केन्द्रीय विद्यालय केन्द्र सरकार चलाती है, अगर उनमें एक-एक उर्दू टीचर रखने का प्रावधान कर दिया जाएगा, तो उर्दू रोजी-रोटी से भी जुड़ेगी और उर्दू के छात्रों को दीक्षा और शिक्षा मिलने का एक साधन बन जाएगा।

†چودھری منور سلیم : مانیور، میں آپ کے مادھیم سے مانتے منتری جی سے کہتا ہوں کہ وہ اردو، جس نے محبت اور انقلاب 'لفظ' کو اپنی کوکھ سے جنم دیا، وہ اردو، آج محبت کی محتاج ہے اور یہ چاہیں، تو اس کو انصاف دے سکتے ہیں۔ نوودنے اور کیندریہ ودھیالیہ، کیندر سرکار چلاتی ہے، اگر ان میں ایک-ایک اردو ٹیچر رکھنے کا پروادھان کر دیا جائے گا، تو اردو روزی روٹی سے بھی جڑے گی اور اردو کے چھاتروں کی دیکشا اور شکشا ملنے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Good question.

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, मुन्ब्वर जी बहुत ही अच्छी उर्दू बोलते हैं, मैं उनकी उर्दू का कायल हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: लेकिन अभी उन्होंने हिन्दी में बोला, उर्दू में नहीं बोला।

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, अभी उन्होंने उर्दू में नहीं बोला, लेकिन जब भी वह भाषण करते हैं, तो मैं उनको सुनता रहता हूँ।

सर, मुद्दा यह है कि he has given a suggestion for action.

श्री डी.पी. त्रिपाठी: शुक्रिया, डिप्टी चेयरमैन साहब। उर्दू के बड़े शायर दाग ने लिखा था कि "नहीं खेल ऐ दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबां पर आते-आते"। इतनी खूबसूरत ज़बान जो हिन्दुस्तान की तहज़ीब और तमहुन की आवाज़ है, उसके मुताल्लिक मरकज़ी हुकूमत क्या कर रही है, इस सिलसिले में मेरे दो सवाल हैं। जो मैं मुक्तसर में, इज़्जतमाब वज़ीर एचआरडी से पूछूंगा।

पहला सवाल यह है कि मरकज़ी हुकूमत ने पिछले दो वर्ष में उर्दू की तरक्की के लिए कौन-से नए तालीमी इदारे खोले हैं? मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि 1998 में इसी पार्लियामेंट के कानून के तहत उर्दू की तरक्की के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में खोली गई। 18 वर्ष में उसमें क्या तरक्की हुई? उसमें यह भी कहा गया था, जो मसला अभी जनाब नदीमुल हक साहब ने उठाया था, असल में वह जोश मलीहाबादी, उर्दू के बड़े शायर ने कहा था कि जो ज़बान रोटी नहीं दे सकती है, वह ज़बान मर जाती है, इसलिए उर्दू को रोजी-रोटी से जोड़ने के लिए भी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम की बात की गई थी। मेरा सवाल यह है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का बजट क्या है और उसमें faculty और student की तादाद क्या है?

श्री प्रकाश जावडेकर: महोदय, जो पहला प्रश्न पूछा उर्दू के विकास के लिए और प्रसार के लिए और उसको रोजी से जोड़ना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं केवल थोड़े में उल्लेख करूंगा कि 1250 बुक्स काउंसिल की तरफ से प्रकाशित की गईं। वे दो मेगज़ीन्स चलाते हैं, "उर्दू दुनिया" और "बच्चों की दुनिया"। 223 मेन्युस्क्रिप्ट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर छपवाया। फिर 753 किताबें, 57 जर्नल्स को बल्क परचेज़ में एप्रूव किया। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वह Urdu Service from UNI का जो समाचार पत्र है और 1054 उर्दू समाचार पत्रों को फ्री न्यूज फीड मिलेगा, इसकी शुरुआत की है। अनेक सेमिनार, लेक्चर्स किए हैं। जिस मुद्दे का आपने जिक्र किया है, इंटरनेशनल कांफ्रेंस भी 5 फरवरी से 7 फरवरी तक हुई और उसकी जो सारी सिफारिशें हैं, उनको हम गहन अध्ययन के साथ विचार करके उससे कोई कार्यक्रम तैयार करें, इस पर काम कर रहे हैं। दूसरा, 200 years of Urdu Journalism इस पर भी कोलकाता में काम हुआ, सेमिनार हुआ। श्रीनगर और पटना में भी बहुत अच्छा हुआ। उर्दू बुक फेयर हर साल की विशेषता है और मैंने कहा कि जो इस साल होगा उसमें मैं जाऊंगा और आप सदस्य भी जाएंगे। तो 1,59,000 students have been awarded diploma under the scheme of Urdu speaking DTP. जो DTP course computer application, business accounting and multi-lingual हैं, ये सीधे-सीधे रोजगार से जोड़ने वाले हैं। मुझे खुशी है कि दो लाख छात्रों ने उसका लाभ लिया है और उनको रोजगार मिला है। तो यह काम हुआ है। Urdu Calligraphy भी बड़े महत्व की है। तो ऐसे ग्राफिक डिजाइन और शॉर्ट Calligraphy इसके लिए भी सेंटर किया है। उसमें 2800 स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। उनको भी सब को रोजगार मिलेगा। उसको भी बहुत अच्छा

समर्थन मिल रहा है। 73,000 स्टूडेंट्स एनरोल किए हैं, कोर्स कम्प्लीट कर रहे हैं। यह नई सुबह है और नई शुरुआत करेंगे और उर्दू और सभी भारतीय भाषाओं का विकास जैसे आप चाहते हैं, वैसे करेंगे।

श्री शिव प्रताप शुक्ल: माननीय उपसभापति जी, देश की स्वतंत्रता के बाद त्रिभाषा फार्मूला के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेज़ी और संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज जो स्थिति है कि प्रदेशों में भी संस्कृत की जिस प्रकार से उपेक्षा हुई है, उसको त्रिभाषा फार्मूले से अलग कर दिया गया। वैसे राज्यों में अपनी एक अन्य भाषा लेकर के त्रिभाषा फार्मूले को बना लिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से इस बात को जानना चाहता हूँ कि क्या संस्कृत के संदर्भ में त्रिभाषा फार्मूले के अन्तर्गत रखने का कोई विचार सरकार करने वाली है या संस्कृत के विकास के लिए सरकार इस प्रकार से कोई उपयोगी सुझाव देने की कृपा करेगी?

श्री प्रकाश जावडेकर: ऐसा है जैसा मैंने कहा, त्रिभाषा फार्मूला barring Tamil Nadu because there was an issue, पर बाकी सभी राज्यों में लागू है और उसमें चॉइस है, उस चॉइस में सभी भारतीय भाषा Modern Indian languages जो 22 संविधान में मान्य की हैं, उन सभी का चॉइस है। छठी कक्षा से दसवीं कक्षा तक वह कौन सी भाषा लेना, यह स्टूडेंट का अधिकार है। सभी भाषाओं के विकास के लिए और जिनको लेना है, उनको उसकी शिक्षा मिले, इसका प्रयास हम हमेशा करते हैं।

Taxpayer education in school syllabus

*198. SHRI ANIL DESAI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether a study was conducted by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) on global best practices in taxpayer education, if so, the details thereof;

(b) whether studies around the world have shown that taxpayer education significantly boosts tax collection; and

(c) if so, what steps the Ministry is taking to include taxpayer education in the school syllabus?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI UPENDRA KUSHWAHA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Department of Revenue of the Ministry of Finance has informed that as per the website of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), a book on 'Building Tax Culture, compliance And Citizenship: A Global Source Book on Taxpayer Education' was launched at the 5th Plenary meeting of the Task Force on Tax and Development held on 2 - 3 November, 2015 in Paris. The book contains taxpayer